ई-माहिती

राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, गुजरात की त्रैमासिक ई - गवर्नेंस पत्रिका

Vibrant GUJARAT 10-12 Jan 2024
Gateway to the Future | 10th Global Summit

mygov मेरी सरकार

G20 भारत 2023 INDIA

Digital India Power To Empower

अप्रैल – जून 2025

सोमनाथ मंदिर

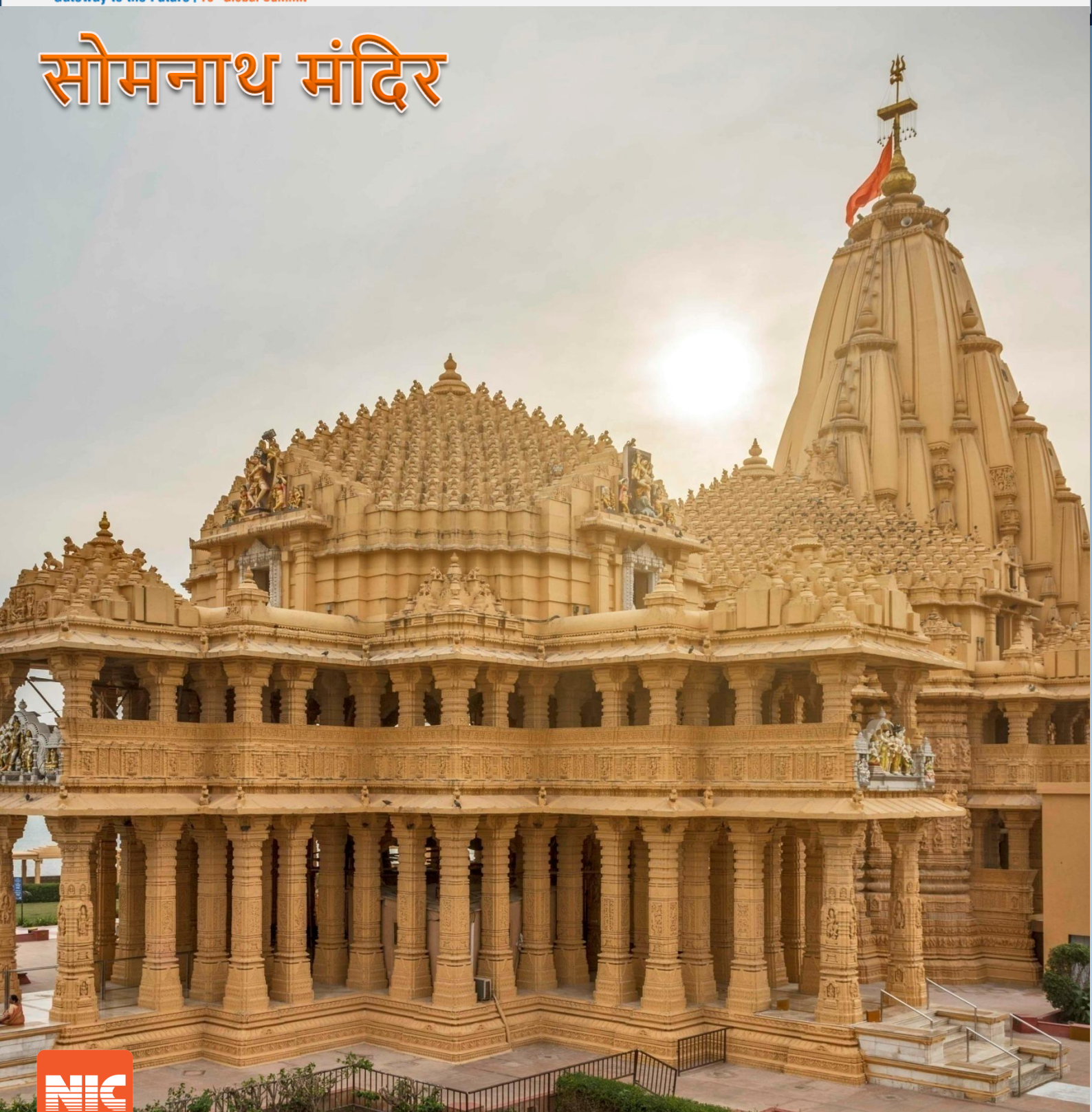

NIC

वेरावल

बाण स्तंभ

सोमनाथ

सोमनाथ
Somnath

जिला एक नजर मे

क्षेत्रफल	3,775 वर्ग किमी
जनसंख्या	9,46,790
साक्षरता दर	76.49 %
ब्लॉक	6
गाँव	345

वेरावल डॉकयार्ड

भालका तीर्थ मंदिर

संपादकीय :

संरक्षक

श्री प्रमोद कुमार सिंह
वैज्ञानिक-जी एवं
राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी गुजरात

संपादकीय टीम

श्री शैलेष खणेशा
वैज्ञानिक-डी एवं
संयुक्त निदेशक (आई.टी.)

श्री कुणाल देराश्री
वैज्ञानिक-सी एवं
उप निदेशक (आई.टी.)

राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र
गुजरात राज्य केंद्र, ब्लॉक 13
द्वितीय तल, सरदार भवन
गांधीनगर, गुजरात 382010

: sio-guj@nic.in
: https://guj.nic.in

अनुक्रमणिका

सार्वजनिक वितरण प्रणाली का आधुनिकीकरण	01
ग्यारहवाँ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस	04
ई-फॉरेंसिक 2.0 एवं ई-प्रॉसिक्यूशन	06
ई-केवाईसी प्रशिक्षण	07
XGN 2.0 पोर्टल एवं SNA स्पर्श	08
राजभाषा नीति के कार्यान्वयन का मूल्यांकन	09

डिजिटल लाइफलाइन:

भारत की सार्वजनिक वितरण प्रणाली का आधुनिकीकरण

गुजरात सरकार यह सुनिश्चित करने के मिशन पर है कि उसकी सार्वजनिक वितरण प्रणाली पहले से कहीं अधिक कुशल और पारदर्शी हो।

जरूरतमंद लोगों को **कम कीमत पर वस्तुएं प्रदान** करने के लिए कई योजनाएं लागू हैं, लेकिन एक लगातार चुनौती यह सुनिश्चित करना रही है कि यह जानकारी हर नागरिक तक पहुंचे।

पुरानी प्रक्रियाएं और जागरूकता की कमी का मतलब था कि कई लाभार्थी उन वस्तुओं और सेवाओं से वंचित रह जाते थे जिनके वे हकदार थे।

अतः **भारत सरकार के खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग** ने सभी राज्यों को सटीकता सुनिश्चित करने और धोखाधड़ी को रोकने के लिए राशन कार्ड से जुड़े आधार नंबरों का ई-केवाईसी सत्यापन पूरा करने के लिए निर्देशित किया।

गुजरात में **खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग** ने इसे गंभीरता से लेते हुए 2023 में लगभग 6.43 करोड़ राशन कार्ड लाभार्थियों के सत्यापन के लिए एक बड़ा अभियान शुरू किया।

इस प्रक्रिया के सफल क्रियान्वयन के लिए, **राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC)** ने **ई-केवाईसी** प्रक्रिया को पूरा करने के लिए कई अभिनव समाधानों की पेशकश करते हुए एक बहु-आयामी डिजिटल रणनीति विकसित की।

नराकास-गांधीनगर राजभाषा गौरव पुरस्कार (कार्यपालक श्रेणी)

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, गांधीनगर की 24वीं छमाही बैठक 28 अप्रैल 2025 को एपेक्स अकादमी, गांधीनगर में श्री सुनील कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में आयोजित हुई।

इसमें विभिन्न केंद्रीय कार्यालयों/संस्थानों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। बैठक में सदस्य कार्यालयों की छमाही रिपोर्ट की समीक्षा की गई तथा नराकास वार्षिक राजभाषा शील्ड 2024-25 का वितरण किया गया।

इस अवसर पर **श्री प्रमोद कुमार सिंह (राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, एनआईसी, गांधीनगर) को राजभाषा गौरव पुरस्कार (कार्यपालक श्रेणी)** से सम्मानित किया गया।

डिजिटल पहचान के चार रास्ते

बायोमेट्रिक-आधारित केवाईसी

एक पारंपरिक और विश्वसनीय तरीका, यह विकल्प **मामलतदार/क्षेत्रीय कार्यालयों** में उपलब्ध है । इसके लिए एक बायोमेट्रिक डिवाइस की आवश्यकता होती है और इसका उपयोग उप-मामलतदारों जैसे अधिकारियों द्वारा लाभार्थियों को व्यक्तिगत रूप से सत्यापित करने के लिए किया जाता है ।

माई राशन मोबाइल ऐप

यह एक नागरिक-केंद्रित एप्लिकेशन है, जो डिजिटल सेल्फ-सर्विस के लिए एक क्रांतिकारी बदलाव है। दिसंबर 2021 में लॉन्च किया गया, यह ऐप नागरिकों को चेहरे की प्रमाणीकरण का उपयोग करके अपना **ई-केवाईसी** पूरा करने की अनुमति देता है, जिसमें किसी अतिरिक्त हार्डवेयर की आवश्यकता नहीं होती है। यह राशन कार्ड के विवरण, उचित मूल्य की दुकानों पर स्टॉक देखने से लेकर शिकायत दर्ज करने और लेनदेन के इतिहास को ट्रैक करने तक की बहुत सारी जानकारी भी प्रदान करता है। आज तक, इस **ऐप को 1.15 करोड़ से अधिक बार डाउनलोड** किया जा चुका है।

बायोमेट्रिक-आधारित वेब पोर्टल

ग्राम पंचायत स्तर पर काम करने वाले **ग्राम स्तरीय उद्यमियों (VCEs)** के लिए, एक समर्पित वेब पोर्टल बनाया गया था। यह तरीका भी एक बायोमेट्रिक डिवाइस का उपयोग करता है, यह सुनिश्चित करता है कि जिन लाभार्थियों का मोबाइल नंबर उनके आधार से लिंक नहीं है, वे भी अपना सत्यापन पूरा कर सकें ।

पीडीएस प्लस मोबाइल एप्लिकेशन

अगस्त 2024 में लॉन्च किया गया, यह **G2G (सरकार से सरकार) एप्लिकेशन** अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए डिज़ाइन किया गया है । यह विभिन्न एमआईएस रिपोर्ट जैसे **ई-केवाईसी** स्थिति, साइलेंट कार्ड सारांश और प्रगति रिपोर्ट प्रदान करता है । इसमें अधिकारियों के लिए नागरिकों का **फेस केवाईसी** करने जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध हैं । इसका उपयोग **VCE, स्कूल स्टाफ, डाकघरों और तालुका कार्यालयों** द्वारा व्यापक रूप से किया गया है, जिन्होंने घर-घर जाकर ई-केवाईसी अभियान चलाया है ।

एक सफल अभियान के आँकड़े

ई-केवाईसी अभियान एक जबरदस्त सफलता रहा है, जो एक बहु-प्लेटफॉर्म दृष्टिकोण की शक्ति को दर्शाता है ।

कुल 6.43 करोड़ राशन कार्ड लाभार्थियों में से, 4.14 करोड़ सदस्यों ने सफलतापूर्वक अपना ई-केवाईसी पूरा कर लिया है ।

सफलता का श्रेय बड़े पैमाने पर सत्यापन के विभिन्न तरीकों को दिया जाता है

यह डिजिटल परिवर्तन सिर्फ संख्याओं के बारे में नहीं है, यह सुनिश्चित करने के बारे में है कि हर नागरिक के पास अपने राशन कार्ड के लिए एक सुरक्षित, डिजिटल पहचान हो,जिससे उन्हें उन लाभों की गारंटी मिले जिनके वे हकदार हैं।

ग्यारहवाँ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस – 2025 का आयोजन

एनआईसी, गुजरात के अधिकारी और कर्मचारीगण ने **21 जून 2025 को ग्यारहवाँ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस** के अवसर पर विभिन्न योग गतिविधियों में उत्साहपूर्वक भाग लिया ।

यह कार्यक्रम गांधीनगर स्थित गुजरात राज्य केंद्र में आयोजित किया गया, जिसमें पंतजलि पीठ, गांधीनगर से 15 वर्षों के अनुभव वाले प्रख्यात योग गुरु **डॉ. कानजी भाई बावरी** और 5 वर्षों के अनुभव वाली योग प्रशिक्षक **डॉ. नेहल देसाई** को अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया ।

कार्यक्रम की शुरुआत डॉ. कानजी भाई बावरी का स्वागत **श्री प्रमोद कुमार सिंह**, वैज्ञानिक-जी एवं राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, एनआईसी, गुजरात तथा **डॉ. नेहल देसाई** का स्वागत श्रीमती जूलेबेन प्रजापति, वैज्ञानिक-डी द्वारा किया गया। इस अवसर पर **एनआईसी** जिला केंद्रों के अधिकारी भी वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के माध्यम से शामिल हुए ।

योग गुरु ने प्रतिभागियों को योग और प्राणायाम के लाभों से अवगत कराया तथा उनके दैनिक जीवन में महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने "**भस्त्रिका प्राणायाम**" और विभिन्न श्वास अभ्यासों का प्रदर्शन करते हुए बताया कि ये अभ्यास कार्यालय समय के दौरान भी तनाव और थकान को दूर करने में सहायक सिद्ध हो सकते हैं ।

गुजरात राज्य केंद्र और जिला कार्यालयों के प्रतिभागियों ने प्रदर्शित आसनों का सक्रिय रूप से अभ्यास किया और योग गुरु के साथ संवाद स्थापित किया, जिससे सत्र को इंटरैक्टिव बनाया गया । ध्यान केवल शारीरिक पहलुओं पर ही नहीं, बल्कि श्वास और गति के सामंजस्य पर भी केंद्रित रहा ।

सत्र के अंत में, **श्री प्रमोद कुमार सिंह**, राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, एनआईसी, गुजरात ने योगाचार्य डॉ. कानजी भाई बावरी और डॉ. नेहल देसाई को इस योग सत्र में उनके मूल्यवान योगदान के लिए विशेष धन्यवाद ज्ञापित किया ।

ग्यारहवाँ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस – 2025

वड़नगर

भरूच

राजकोट

पोरबंदर

अहमदाबाद

बनासकांठा

वड़नगर

e-Forensic 2.0: न्याय में तेजी

नए आपराधिक कानूनों **(BNS, BNSSS और BSA-2023)** के कार्यान्वयन के साथ, सुव्यवस्थित न्यायिक प्रक्रियाओं की आवश्यकता पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है । एनआईसी गुजरात टीम के तकनीकी सहयोग से विकसित, नया e-Forensic 2.0 प्लेटफॉर्म, राज्य की फोरेंसिक प्रयोगशालाओं के लिए एक क्रांतिकारी टूल है । यह एप्लिकेशन फोरेंसिक प्रयोगशालाओं, पुलिस और अदालतों के बीच निर्बाध डेटा साझाकरण को सक्षम बनाता है ।

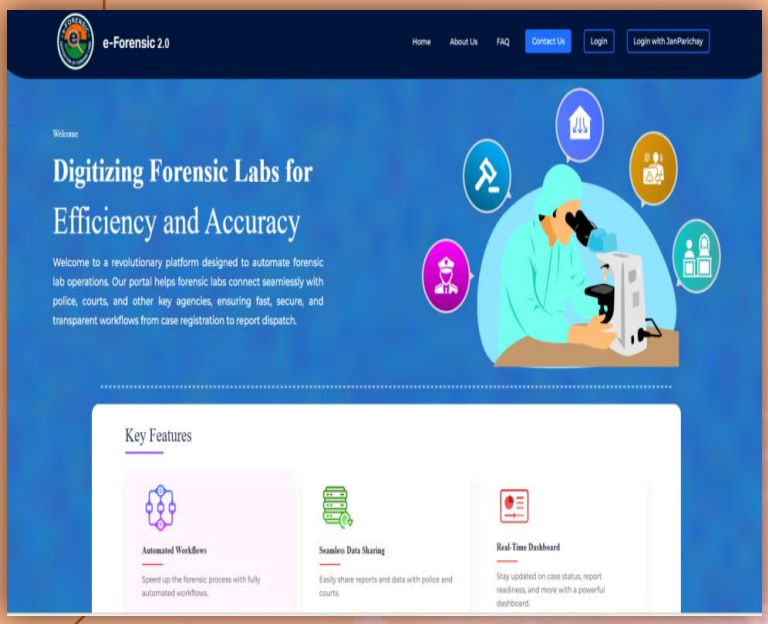

गुजरात में **फोरेंसिक विज्ञान निदेशालय (DFS)** द्वारा **1 जून 2025** से उपयोग के लिए लॉन्च किया गया , यह एप्लिकेशन फोरेंसिक नमूनों की पूरी ट्रैकिंग प्रदान करता है और परीक्षा अधिकारियों के ई-हस्ताक्षर के साथ सुरक्षित, ई-हस्ताक्षरित रिपोर्ट बनाने की सुविधा प्रदान करता है । एनआईसी गुजरात टीम ने पहले ही DFS के लगभग 250 वैज्ञानिक अधिकारियों को परिचालन प्रशिक्षण प्रदान कर दिया है ।

e-Prosecution : पब्लिक प्रॉसिक्यूटर को सशक्त बनाना

ICJS परियोजना के एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में, e-Prosecution एप्लिकेशन पब्लिक प्रॉसिक्यूटर के लिए एक शक्तिशाली नया डिजिटल उपकरण है । एनआईसी द्वारा विकसित और गुजरात भर के सभी पब्लिक प्रॉसिक्यूटर कार्यालयों में तैनात, वेब और मोबाइल एप्लिकेशन ऑनलाइन केस ट्रैकिंग की अनुमति देते हैं, जिसमें ड्राफ्ट चार्जशीट, कानूनी राय और दैनिक केस कार्यवाही अपलोड करना शामिल है ।

एनआईसी गुजरात ने **700 से अधिक कानूनी पेशेवरों को तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान किया** है, यह सुनिश्चित करते हुए कि वे नए आपराधिक कानूनों के तहत इस उपकरण का लाभ उठाने के लिए अच्छी तरह से सुसज्जित हैं ।

डिजिटल कार्यबल को सशक्त बनाना

महत्वाकांक्षी **ई-केवाईसी** अभियान की सफलता सुनिश्चित करने के लिए, **एनआईसी** और खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग ने एक व्यापक प्रशिक्षण पहल पर सहयोग किया।

BISAG प्लेटफॉर्म का लाभ उठाते हुए, उन्होंने **सितंबर 2024 से जुलाई 2025 तक साप्ताहिक प्रशिक्षण सत्रों** की एक श्रृंखला आयोजित की, जो नागरिकों से लेकर सरकारी अधिकारियों तक उपयोगकर्ताओं की एक विस्तृत श्रृंखला तक पहुंची।

इन सत्रों को दो भागों में विभाजित किया गया था **वीडियो और पीपीटी जैसी प्रशिक्षण सामग्री** का उपयोग करके एक संरचित प्रस्तुति, जिसके बाद एक लाइव प्रश्नोत्तर सत्र होता था जहां अंतिम उपयोगकर्ता अपने प्रश्नों के साथ कॉल कर सकते थे। इन सत्रों को YouTube पर भी लाइव स्ट्रीम किया गया था, जिससे उनकी पहुंच अधिकतम हो गई।

अंतिम उपयोगकर्ताओं के साथ यह सीधा जुड़ाव बहुत प्रभावी साबित हुआ, न केवल ई-केवाईसी पूरा होने की संख्या बढ़ाने में, बल्कि वास्तविक समय में तकनीकी मुद्दों को संबोधित करने में भी। अभियान की सफलता, जिसमें **4.14 करोड़ ई-केवाईसी पूरे हुए**, इस समर्पित प्रशिक्षण और सहायता का सीधा परिणाम है।

सरकारी फंड प्रवाह का पुनर्नवीनीकरण

SNA-SPARSH पहल इस बात का एक प्रमाण है कि कैसे डिजिटल एकीकरण सरकारी प्रक्रियाओं में क्रांति ला सकता है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए धन के संवितरण को सुव्यवस्थित करना है, जिसमें सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (PFMS), राज्य एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (IFMS), और भारतीय रिजर्व बैंक के ई-कुबेर को जोड़ा गया है। यह "जस्ट-इन-टाइम" (JIT) दृष्टिकोण पारदर्शिता और राजकोषीय अनुशासन सुनिश्चित करता है।

जब **IFMS** और **PDS** टीमों ने प्रक्रिया को स्वचालित करने के लिए अपने मौजूदा डेटा फ्रेमवर्क का लाभ उठाया, तो एक सफलता मिली।

उन्होंने एक ऐसी प्रणाली का निर्माण किया जो अनुपालन वाले डेटासेट को स्वतः उत्पन्न कर सकती थी और उन्हें सीधे **JSON API** के माध्यम से **SNA-SPARSH** प्लेटफॉर्म पर भेज सकती थी, जिससे मैनुअल डेटा प्रविष्टि की आवश्यकता पूरी तरह समाप्त हो गई।

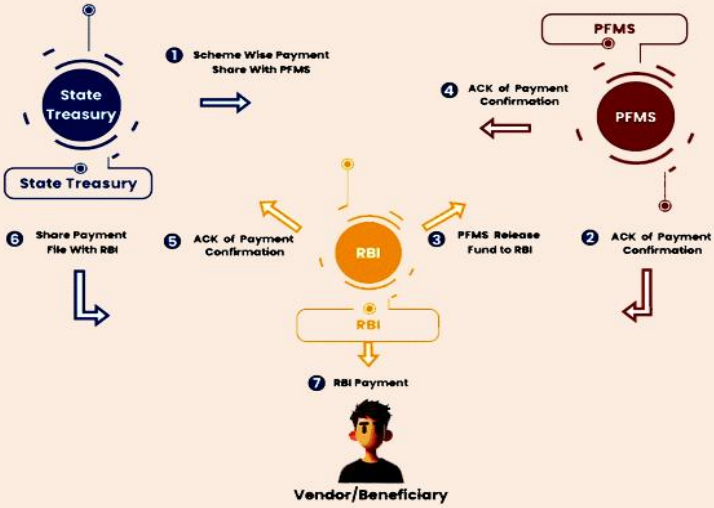

इसके अलावा, सिंगल-मेकर, सिंगल-चेकर लॉगिन ने अनुमोदन को सुव्यवस्थित किया, जिससे कार्यभार हफ्तों से घटकर कुछ ही घंटों का हो गया।

यह नवाचार दर्शाता है कि कैसे प्रक्रिया पुनर्गठन + डिजिटल एकीकरण जटिल, उच्च-मात्रा वाले सरकारी फंड प्रवाह को कुशल, अनुपालन योग्य और प्रतिलिपि प्रस्तुत करने योग्य मॉडल में बदल सकता है, जो प्रौद्योगिकी-संचालित सुधारों के लिए एक बेंचमार्क स्थापित करता है।

XGN 2.0: एक हरियाली भरा भविष्य, डिजिटल रूप से पुनर्निर्मित

राज्य में पर्यावरणीय शासन के लिए एक महत्वपूर्ण कदम में, माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस, 5 जून 2025 को, नए सिरे से बनाए गए eXtended Green Node (XGN 2.0) पोर्टल को लॉन्च किया गया।

XGN पोर्टल गुजरात प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (GPCB) के लिए एक महत्वपूर्ण ई-गवर्नेंस समाधान है, जिसे NIC, गुजरात द्वारा डिज़ाइन और विकसित किया गया है। 2008 में अपनी स्थापना के बाद से, पोर्टल ने पर्यावरणीय मंजूरी के लिए आवश्यक ऑनलाइन सेवाएं प्रदान की हैं, जिससे किसी भी औद्योगिक इकाई की स्थापना या मौजूदा इकाई के विस्तार से पहले प्रदूषण को रोकने और नियंत्रित करने में मदद मिली है।

आधुनिकीकरण की आवश्यकता को पहचानते हुए, GPCB ने हाल ही में एक व्यापक व्यावसायिक प्रक्रिया पुनर्गठन (BPR) अभ्यास किया। इस BPR के परिणामों को शामिल करने के लिए, NIC गुजरात टीम ने पुराने XGN पोर्टल को नए XGN 2.0 संस्करण में अपग्रेड करने के लिए एक बड़ी परियोजना शुरू की। यह नया संस्करण हितधारकों के लिए कई बढ़ी हुई सेवाएं प्रस्तुत करता है, जो प्रणाली को समकालीन प्रक्रियाओं और नियमों के साथ संरेखित करता है।

इस लॉन्च कार्यक्रम में अन्य गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति रही, जिसमें श्री मुलुभाई बेरा, माननीय मंत्री, वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन, गुजरात सरकार, और श्री मुकेशभाई पटेल, माननीय राज्य मंत्री, वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन, गुजरात सरकार शामिल थे।

लॉन्च कार्यक्रम में:

- **श्री संजीव कुमार**
  आईएएस, प्रधान सचिव, वन और पर्यावरण विभाग, गुजरात सरकार

- **श्री आर बी बराड़**
  आईएएस, अध्यक्ष, जीपीसीबी

- **श्री प्रमोद कुमार सिंह**
  वैज्ञानिक-जी एवं एसआईओ, एनआईसी गुजरात

- **श्री पंकज के. पाठक**
  वैज्ञानिक-एफ, एनआईसी, गुजरात

- **श्री रमाकांत सोनी**
  वैज्ञानिक-सी, एनआईसी, गुजरात

एनआईसी गुजरात में राजभाषा कार्यान्वयन का मूल्यांकन

- राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी), गुजरात राज्य केंद्र ने हाल ही में अपनी राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के व्यापक निरीक्षण के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) के उच्च-रैंकिंग अधिकारियों का स्वागत किया।

- 30 जून 2025 को, सुश्री तुलिका पांडे, वैज्ञानिक 'जी' और समूह प्रमुख (राजभाषा), और श्री शिव कुमार निगम, संयुक्त निदेशक (राजभाषा), का स्वागत श्री प्रमोद कुमार सिंह, राज्य सूचना अधिकारी, एनआईसी गुजरात और राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष, और समिति के सदस्यों ने किया।

- निरीक्षण में कर्मचारियों के सेवा अभिलेखों, फाइलों, रजिस्टरों, नोटिंग, सामान्य आदेशों, विज़िटिंग कार्डों, नेम प्लेटों, रबर स्टैंपों, लेटर हेडों आदि की विस्तृत समीक्षा शामिल थी, ताकि भारत सरकार की नीतियों का अनुपालन सुनिश्चित हो सके। निरीक्षण अधिकारियों ने राजभाषा में कार्यालय द्वारा किए गए कार्यों और प्रयासों की सराहना करते हुए संतोष व्यक्त किया।

- संयुक्त निदेशक (राजभाषा) ने कार्यालय परिसर और कर्मचारियों के बैठने की व्यवस्था का भी निरीक्षण किया। उन्होंने राजभाषा अधिनियम 1963 और राजभाषा नियम 1976 के तहत कई महत्वपूर्ण उप-नियमों के बारे में भी विस्तार से चर्चा की।

Editorial:

Patron:

Shri Pramod Kumar Singh
Scientist-G &
State Informatics Officer Gujarat

Editorial Team :

Shri Shailesh Khanesha
Scientist-D & Joint Director (IT)

Shri Kunal Derashri
Scientist-C & Deputy Director (IT)

National Informatics Centre
Gujarat State Centre, Block 13
2nd Floor, Sardar Bhavan
Gandhinagar, Gujarat 382010

: sio-guj@nic.in

: https://guj.nic.in

INDEX

Modernization of India's Public Distribution System	01
11th International Yoga Day	04
e-Forensic 2.0 and e-Prosecution	06
e-KYC Training Campaign	07
XGN 2.0 Portal and SNA SPARSH	08
Official Language Implementation Appraised	09

Digital Lifeline:

Modernization of India's Public Distribution System

The **government of Gujarat** is on a mission to ensure that its public distribution system is more efficient and transparent than ever before. While numerous schemes are in place to provide **low-cost commodities** to those in need, a persistent challenge has been ensuring this information reaches every citizen.

Outdated processes and a **lack of awareness** meant many beneficiaries were missing out on the goods and services they were entitled to

In response, the **Department of Food and Public Distribution, Government of India**, issued a directive to all states: complete the e-KYC verification of Aadhaar numbers linked to ration cards to ensure accuracy and prevent fraud4.

The Food, Civil Supplies and Consumer Affairs Department in Gujarat took this mandate head-on, launching a massive campaign in 2023 to verify around 6.43 crore ration card beneficiaries. To tackle a project of this scale, the **National Informatics Centre (NIC)** developed a multi-pronged digital strategy, offering several innovative solutions to complete the e-KYC process.

Narakas - Gandhinagar Official Language Gaurav Award (Executive Category)

The 24th half-yearly meeting of the Town Official Language Implementation Committee, Gandhinagar, was held on 28 April 2025 at Apex Academy, Gandhinagar, under the chairmanship of Mr. Sunil Kumar Sinha.

Representatives of various Central Government offices/institutions participated in the meeting. The half-yearly reports of member offices were reviewed, and the Narakas Annual Official Language Shield 2024-25 was distributed.

On this occasion, Mr. Pramod Kumar Singh (State Informatics Officer, NIC, Gandhinagar) was honored with the Official Language Gaurav Award (Executive Category).

Four Pathways to Digital Identity

Biometric-Based KYC

A traditional and reliable method, this option is available at **Mamlatdar/Zonal offices**. It requires a biometric device and is used by officials like Deputy Mamlatdars to verify beneficiaries in person.

My Ration Mobile App

A citizen-centric application, this is a game-changer for digital self-service. Launched in December 2021, the app allows citizens to complete their own **e-KYC** using facial authentication, with no additional hardware needed. It also provides a wealth of information, from viewing ration card details and stock at Fair Price Shops to filing grievances and tracking transaction history. To date, the **app has been downloaded 1.15 crore times**.

Biometric-Based Web Portal

For **Village-level entrepreneurs (VCEs)** operating at the Gram Panchayat level, a dedicated web portal was created. This method also uses a biometric device, ensuring that beneficiaries without a mobile number linked to their Aadhaar can still complete their verification.

PDS Plus Mobile Application

Launched in August 2024, this **G2G (government-to-government) application** is designed for officials and staff. It offers valuable MIS reports and the ability to perform **e-KYC** for citizens using face authentication. It has been widely adopted by **VCEs,** school staff, and post office workers, who have used it to conduct door-to-door e-KYC drives

Statistics of a Successful Campaign

The e-KYC campaign has been a tremendous success, demonstrating the power of a multi-platform approach.

Out of the total 6.43 crore ration card beneficiaries, 4.14 crore members
successfully completed their e-KYC.

The success is largely attributed to the various verification methods:

This digital transformation is not just about numbers; it is about ensuring that every citizen has a secure, digital identity for their ration card, guaranteeing them access to the benefits they are entitled to.

Celebration of 11th International Day of Yoga – 2025

NIC, Gujarat's Officers and Staff enthusiastically participated in various yoga activities on the **occasion of the 11th International Day of Yoga on June 21, 2025**. The event was held at the Gujarat State Centre in Gandhinagar, where Dr. Kanjibhai Bawari, a renowned Yoga Guru with 15 years of experience from Patanjali Pith, Gandhinagar and Dr. Nehal Desai, a yoga instructor with 5 years of experience in Gandhinagar were invited as guests.

The function commenced with a warm welcome extended to **Dr. Kanjibhai Bawari by Shri Pramod Kumar Singh, DDG & SIO, NIC, Gujarat and Dr. Nehal Desai by Mrs. Juleeben Prajapati, Scientist-D**. The event was also attended by officers from NIC District Centres via virtual conference.

The Yoga Guru enlightened participants on the benefits of yoga and pranayama, highlighting their significance in daily life.
Demonstrating "**Bhastrika Pranayama**" and various breathing exercises, he showed how these practices can alleviate stress and fatigue, even during office hours.

Participants from the Gujarat State Centre and District Offices actively followed the demonstrated postures and engaged with the Yoga Guru, making the session interactive. The focus was not just on the physical aspects but also on the importance of synchronizing breath with movement.

At the end of the session, **Shri Pramod Kumar Singh**, **State Informatics Officer, NIC**, Gujarat extended a special vote of thanks to Yogacharya Dr. Kanjibhai Bawari and Dr. Nehal Desai for their valuable contributions to the yoga session.

Vadnagar

Bharuch

Rajkot

Porbandar

Ahmedabad

Banaskantha

Vadnagar

e-Forensic 2.0: Accelerating Justice

With the implementation of the **new criminal laws (BNS, BNSSS & BSA-2023),** the need for streamlined judicial processes is more critical than ever. The new e-Forensic 2.0 platform, developed with technical support from the NIC Gujarat Team, is a revolutionary tool for the state's forensic laboratories.

The application enables seamless data sharing between forensic labs, police, and courts. Launched for use by the **Director of Forensic Science (DFS)** in Gujarat on June 1, 2025,

the application provides end-to-end **tracking of forensic samples and offers secure, e-signed report** generation. The NIC Gujarat Team has already provided operational training to nearly 250 scientific officers from the DFS.

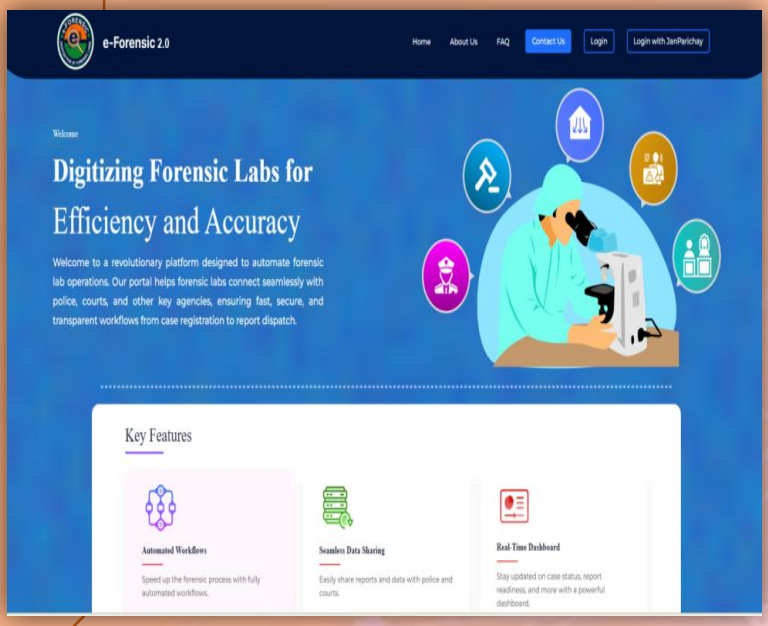

e-Prosecution: Empowering Public Prosecutors

As a vital component of the **ICJS Project**, the e-Prosecution application is a powerful new digital tool for public prosecutors. Developed by NIC and deployed across all Public Prosecutor Offices in Gujarat, the web and mobile applications allow for online case tracking, including the uploading of **draft charge sheets, legal opinions, and daily case** proceedings.

NIC Gujarat has provided technical **training to over 700 legal professionals**, ensuring they are well-equipped to leverage this tool under the new criminal laws

Empowering the digital workforce

To ensure the **success of the ambitious e-KYC campaign**, NIC and the Food, Civil Supplies and Consumer Affairs Department collaborated on a comprehensive training initiative.

Leveraging the BISAG platform, they conducted a series of weekly training sessions from September 2024 to July 2025, reaching a wide range of users, from citizens to government officials.

These sessions were divided into two parts: a structured **presentation using training materials like videos and presentations**, followed by a live Q&A session where end-users could call in with their queries. The sessions were also live-streamed on YouTube, maximizing their reach.

This direct engagement with end-users proved to be highly effective, not only in increasing the number of e-KYC completions but also in addressing technical issues in real-time. The success of the campaign, which **saw 4.14 crore e-KYC** completions, is a direct result of this dedicated training and support.

Recycling of government fund flows

The **SNA-SPARSH** initiative is a testament to how digital integration can revolutionize government processes. The program aims to streamline the disbursement of funds for Centrally Sponsored Schemes, linking the **Public Financial Management System (PFMS), State Integrated Financial Management System (IFMS), and the Reserve Bank** of India's e-Kuber. This **"Just-in-Time"** (JIT) approach ensures transparency and fiscal discipline.

For **Gujarat's Food, Civil Supplies and Consumer Affairs Department**, this reform was a game-changer. The department is responsible for a monthly disbursement of approximately **₹17 crore in commissions** and handling charges to nearly **16,000 Fair Price** Shop owners 47. The manual process previously required over **64,000** individual data entries each month—a time-consuming and error-prone task.

The breakthrough came when the IFMS and PDS teams leveraged their existing data framework to automate the process.

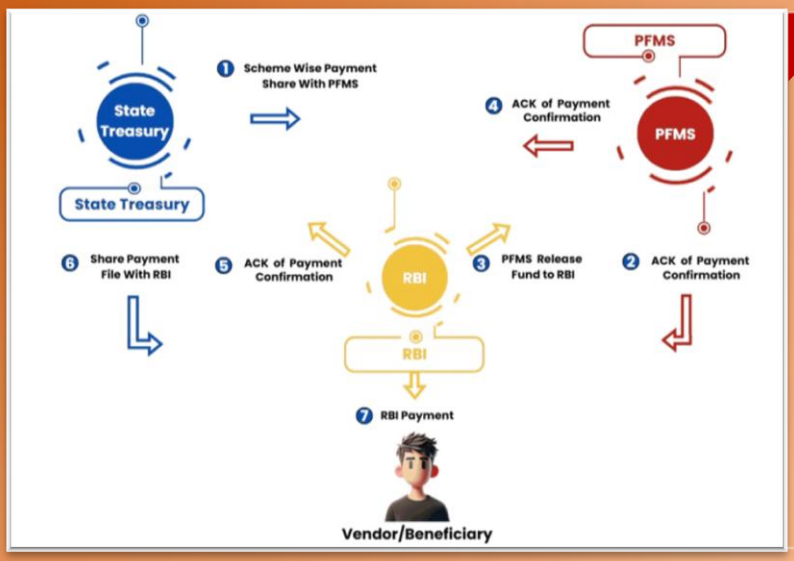

They built a system that could auto-generate compliant datasets and push them directly to the **SNA-SPARSH platform via JSON APIs**, completely eliminating the need for manual data entry.

This innovation, along with a streamlined **"single-maker, single-checker" approval process, has reduced the workload from weeks to a matter of hours**, showcasing the transformative power of digital integration.

XGN 2.0: A greener future, digitally reinvented

In a landmark move for environmental governance in the state, the revamped **eXtended Green Node (XGN 2.0) portal** was launched on World Environment **Day, June 5, 2025, by the Honorable Chief Minister of Gujarat, Shri Bhupendra Patel.**

The **XGN portal is a critical e-Governance solution for the Gujarat Pollution Control Board (GPCB)**, designed and developed by the NIC, Gujarat. Since its inception in 2008, the portal has provided essential online services for environmental clearance, helping to prevent and control pollution.

Recognizing the need for modernization, the GPCB recently conducted a comprehensive Business Process Reengineering (BPR) exercise. To incorporate the outcomes of this BPR, the NIC Gujarat team undertook a major project to upgrade the old XGN portal to the new XGN 2.0 version.

This new version introduces several enhanced services for stakeholders, aligning the system with contemporary processes and regulations.

The launch event was graced by other distinguished dignitaries, including Shri Mulu bhai Bera, Honorable Minister for Forest, Environment & Climate Change, and Shri Mukesh bhai Patel, Honorable State Minister for Forest, Environment & Climate Change.

At the Launch Event:

Shri Sanjeev Kumar
IAS, Principal Secretary, Forest & Environment Department, Govt. of Gujarat

---

Shri R B Barad
IAS, Chairman, GPCB

Shri Pramod Kumar Singh
Scientist-G & SIO, NIC, Gujarat

Shri Pankaj K. Pathak
Scientist-F, NIC, Gujarat

Shri Rama Kant Soni
Scientist-C, NIC, Gujarat

Official Language Implementation Appraised at NIC Gujarat

The National Informatics Centre (NIC), Gujarat Gujarat State Centre, recently welcomed high-ranking officials from the **Ministry of Electronics and Information Technology (MeitY)** for a comprehensive inspection of its Official Language policy implementation.

On June 30, 2025, Ms. Tulika Pandey, Scientist 'G' & Group Head, and Shri Shiv Kumar Nigam, Joint Director (Official Language), were welcomed by Shri Pramod Kumar Singh, State Informatics Officer and Chairman of the Official Language Implementation Committee, and other members.

The inspection included a detailed review of various office documents, from service books to letterheads, ensuring compliance with Government of India's policies.

The visiting officials expressed their satisfaction and appreciated the efforts made by the NIC Gujarat team. The discussion also delved into key sub-rules of the Official Language **Act 1963 and its 1976 rules, reinforcing the commitment to official language implementation.**

Veraval Port

Saurashtra, Gujarat

वेरावल बंदरगाह

सौराष्ट्र, गुजरात

Veraval, a bustling town on the Arabian Sea, is renowned for its vibrant **fishing industry** and role as one of India's largest seafood processing hubs. The town serves as the **gateway to Somnath Temple**, one of the twelve sacred Jyotirlingas dedicated to Lord Shiva, attracting countless pilgrims each year. Historically, Veraval functioned as a **seaport for Haj pilgrims**, linking India with distant lands. Today, its charm extends beyond trade and devotion, offering visitors **serene beaches, historical sites, and coastal beauty**. Blending spirituality, livelihood, and heritage, Veraval stands as a unique destination that reflects Gujarat's rich culture and traditions.

E-MAHITI

An e-GOVERNANCE MAGZINE FROM NATIONAL INFORMATICS CENTRE, GUJARAT

April – June 2025

Vibrant GUJARAT 10-12 Jan 2024
Gateway to the Future | 10th Global Summit

mygov मेरी सरकार

G20 भारत 2023 INDIA

Digital India
Power To Empower

Somnath Temple

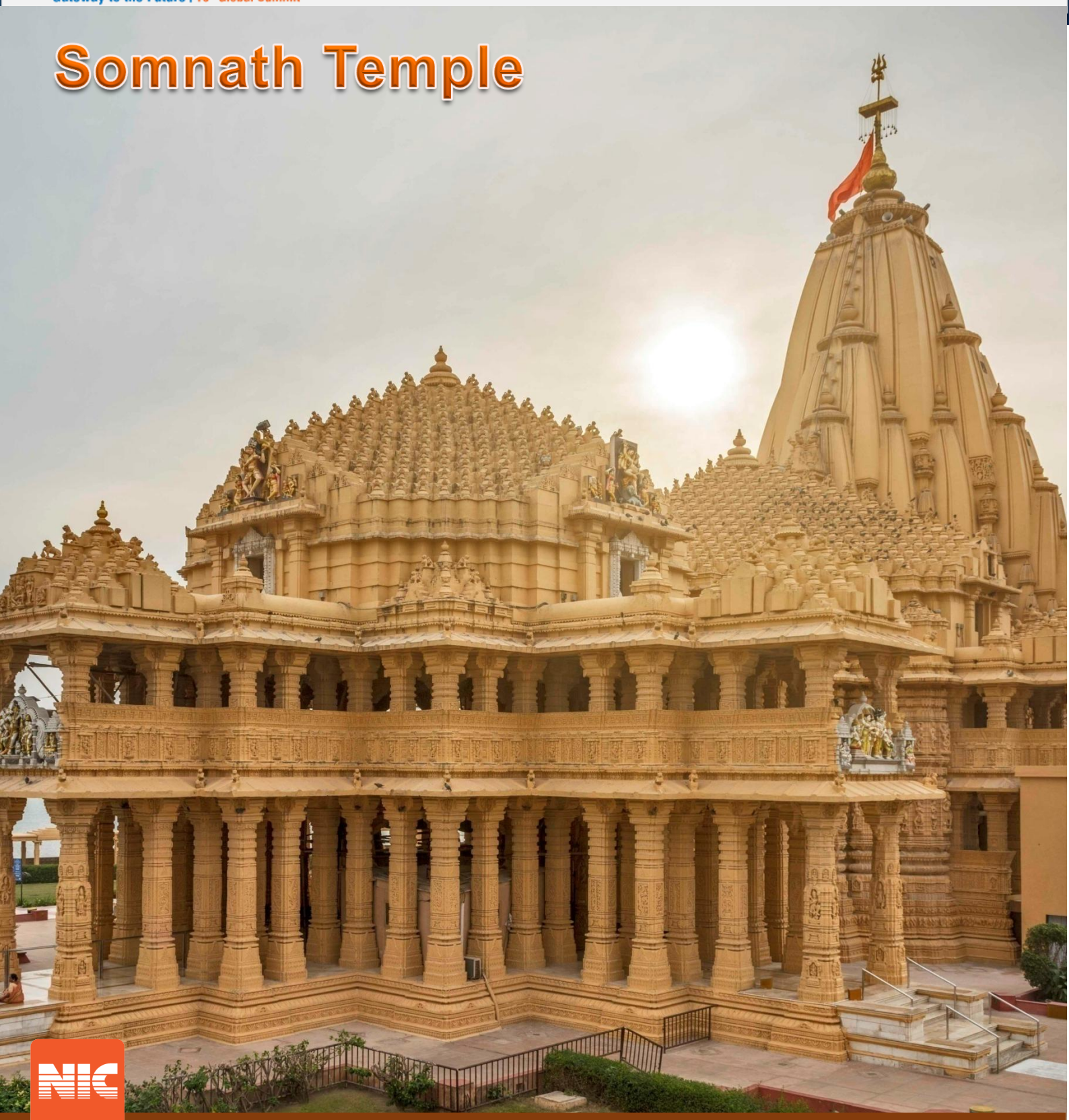

NIC